



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 228) पटना, बृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 जनवरी 2015

सं0 22 नि0 सि0 (पट0)—3—14/2013/81—श्री सुनील कुमार (आई0डी0—4462) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के उक्त पद पर पदस्थापन अवधि में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या—51 दिनांक 10.01.2014 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक—98 दिनांक 21.01.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी:—

**आरोप—1—** आपके द्वारा दिनांक 28.06.2013 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर योगदान दिया गया। विभागीय कार्यों के क्रम में आपकी खोज की गई, किन्तु आप योगदान देने के पश्चात् से लगातार अनुपस्थित पाये गये, जिससे सरकारी कार्यों के निष्पादन में बाधा हुई।

**आरोप—2—** ग्रामीण विकास विभाग में तकनीकी कोषांग प्रभारी श्री तुलसी राम, कार्यपालक अभियंता द्वारा संचिका संख्या—ग्रा0वि0—1 स्था0(रा0प0) 32/2013 पर प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 28.06.2013 के बाद आप उनके सम्पर्क में नहीं रहे हैं।

**आरोप—3—** ग्रामीण विकास विभाग में प्रत्येक मंगलवार को विभागीय पदाधिकारी की बैठक होती है, जिसमें आप बराबर अनुपस्थित रहे हैं। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 29.08.13 एवं 12.09.13 की तकनीकी कोषांग के कार्यों में समीक्षात्मक बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का आदेश संख्या—155557 दिनांक 12.07.13 के द्वारा आपको इंदिरा आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना इत्यादि संबंधी कार्य आवंटित है। किन्तु आपके द्वारा उक्त में से किसी भी कार्य का आज तक निष्पादन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आप जान बूझकर कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। आपके द्वारा विभागीय कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या—1, 2 एवं 3 को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक—1250 दिनांक 03.09.2014 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण—पृच्छा किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण—पृच्छा का जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण—पृच्छा का जवाब में मुख्य रूप से कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग में योगदान देने के पश्चात्

लगातार कार्यालय में उपस्थित रहे हैं। डिप्रेशन के चलते मात्र दो (2) बैठक में भाग नहीं लिये हैं। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा के जवाब में पूर्व में बचाव बयान में कही गयी बातों को दुहराया गया है जिसके आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाया गया है। इनके द्वारा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया:-

(1) निन्दन वर्ष 2013-14

(2) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक

(3) निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु इस अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी एवं इसे सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी।

वर्णित स्थिति में श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है:-

(1) निन्दन वर्ष 2013-14

(2) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक

(3) निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु इस अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी एवं इसे सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सतीश चन्द्र झा,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 228-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>